



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

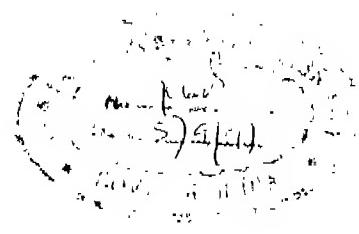
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 110 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 1997/ज्येष्ठ 21, 1919

No. 110 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 1997/JYAISHTHA 21, 1919

व्यापिन्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 1997

विषय: यू.एस.ए., कनाडा तथा रूस से अखबारों कागज के आयात संबंधी पाटनरोधी जाँच—प्रारंभिक निष्कर्ष

सं. 21/एडीडी/96:—1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके सीमाशुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन तथा वसूली एवं क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. क्रियाविधि

1. वर्तमान जाँच के बारे में निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई गई है;
- क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) को उपर्युक्त नियमों के तहत इंडियन न्यूज़प्रिट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन से लिखित रूप में याचिका प्राप्त हुई जिसमें यू.एस.ए., कनाडा तथा रूस मूल के अथवा वहाँ के नियार्थित अखबारों कागज की डिपिंग का आरोप लगाया गया है।
- ख. आवेदन की प्रारंभिक जाँच के कुछेक कमियों का पता चला था जो याचिकाकर्ता को अतला दी गई थी।
- ग. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने यू.एस.ए., कनाडा और रूस (जिन्हें इसके बाद संबंधित देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहाँ से नियार्थित कथिक रूप से डम्प किए गए आयातों के विरुद्ध जाँच शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकारी ने डिपिंग आरोप के प्राप्त होने के बारे में उपनियम 5 (5) के अनुसार जाँच को शुरू करने के लिए कार्रवाई के बारे में संबंधित देशों के दूतावासों को सूचित कर दिया है।

- घ. प्राधिकारी ने दिनांक 20-12-1996 को सक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण मै प्रकाशित हुई जिसमें सीमांशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अधिसूचना -I के अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत शू स्त स, कनाडा तथा स्त के मूल के अध्या वहाँ के निर्यातित अखबारी कागज के आयात के संबंध में पाटनरोधी कार्रवाई शुरू की थी।
- ङ. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों और जिनके संबंध में छ्याँरे याधिकार्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे तथा उपोग पौरसंघों को प्रेषित की थी तथा नियम 6॥२॥ के अनुसार मैं उन्हें 40 दिन के भीतर लिखित मैं अपने विधारों को भेजने का अप्सर प्रदान किया गया था।
- घ. प्राधिकारी ने भारत में अखबारी कागज के ज्ञात आयात को को सार्वजनिक सूचना की प्रतियाँ प्रेषित की थी और उन्हें इस पत्र की तारीख के 40 दिन के भीतर लिखित मैं अपने विधार भेजने की सलाह दी थी।
- छ. केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमांशुल्क बोर्ड सी बी ई सी को जांच की अधिक के लिए अपेक्षित सभी बिल प्राविष्टियों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया बहरहाल सी बी ई सी में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।
- ज. प्राधिकारी ने उक्त नियम 6॥३॥ के अनुसार संबंधित देशों के दूतावासों तथा ज्ञात निर्यातकों को याचिका की प्रतियाँ भेजी थी।
- झ. प्राधिकारी ने निम्नलिखित निर्यातकों के अपेक्षित सूचना जानने के लिए प्रश्नावलीयाँ भी भेजी थी;
- स्थीर्बी प्राइस इंक, कनाडा
  - स्थीटिबी प्राइस शेल्स कारपोरेशन, यूए स्त० स०
  - बोयाटर मर्सी पेपर कंपनी लिमिटेड कनाडा
  - तौसी ऐम्प्युन इंक, कनाडा
  - डाक्सोपा फोरेस्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड कनाडा
  - स्टोरा फोरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कनाडा
  - स्काईटिपकार फोरेस्ट कम्पलेक्शन, स्त
  - कोडोपागा पल्ट्य स्टड पेपर कम्पाइन, स्त

- सौली का मूर्क पत्त्य स्टड पेपर कम्बाइन, स्स
- बालखना पत्त्य स्टड पेपर कम्बाइन, स्स

निम्नलिखित निर्णयों ने बढ़ी हुई समयावधि के भीतर प्रश्नावली के उत्तर में

- रबीटीबी-प्राइस इंक [इसके बाद इन्हें रबीटीबी कहा जास्ता] ।
- स्टोन क्सोलिडेट कारपोरेशन, यू० स्स० ए०
- [इसके बाद इन्हें स्टोन क्सोलिडेट कहा जास्ता] ।

- अ० अनेक निर्णयों, आयातकों तथा उपभोक्ताओं ने समयवृद्धि के लिए अनुरोध किया प्राप्तिकारी ने २८-२-७७ तक इस पृष्ठ की अनुमति दी ।
- ट० नई दिल्ली में यू० स्स० ए०, कनाडा तथा स्स के दूतावासों को नियम ६॥२॥ के तहत जाय शुरू करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचना दी थी कि वे अपने-अपने देश के निर्णयों/ उपजक्ताओं को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें । फ्रं की प्रति याचिका तथा निर्णयों की प्रश्नावली इस निर्णयों उपजक्ताओं की सूची के साथ दूतावासों को भी भेज दी गई थी ।
- ठ० भारत में अखबारी कागज के इस अनुबंधित सेंटो तथा आयातकों को प्रश्नावली देनी गई जिसमें नियम ६॥४॥ के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी ।
- ड० भारत में अखबारी कागज के अनेक आयातकों/उपभोक्ताओं ने प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति, प्रश्नावली तथा/या उत्तर देने के लिए समयवृद्धि का अनुरोध किया था २८ फरवरी, १९७७ तक समयवृद्धि की अनुमति मिली थी/तथापि, प्राप्तिकारी ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया था कि स्ता कोई प्राक्षान नहीं है कि सभी इस्पृष्ठ पार्टीयों के उत्तर की प्रतीक्षा की जाए अर्था उन इस्पृष्ठ पार्टीयों को अतिरिक्त समय दिया जाए जिनसे प्राप्तिकारी ने प्रथम दूतावास कोई जानकारी नहीं मांगी अपितु वे अपनी ओर से अपना दब्बाव करने के इस्पृष्ठ हैं । अतः प्रश्नावली उन सभी पार्टीयों को नहीं देनी गई जिन्होंने अनुरोध किया था हालाँकि प्रारंभिक अधिसूचना की एक प्रति भेज दी गई थी ।
- इ० घरेलू उद्योग से संबंधित जानकारी याचिकाकर्ता से मांगी गई थी । याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की;

- मैसूर पेपर मिल्स लिंग [मैसूर या सम पी सम],
- नेपा लिंग [नेपा]
- तमिलनाडु न्यूजप्रिंट स्टड पेपर लिंग [टी सन पी सल]
- हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिंग [सच सन सल]

ण प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जांच परिणामके लिए जरूरी समझी गई जानकारी का सत्यापन किया।

त सामान्य स्प से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर लागत जांच भी की गई ताकि उत्पादन की अधिकतम लागत तथा भारत में अखबारी कागज के निर्माण सं बिक्री की लागत का पता लगाया जा सके जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या डीपिंग मार्लिन से कम प्रतिपादन मूल्क लगाना घरेलू उद्योग की क्षमिता को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

थ यह जाँच । अप्रैल, 1996 से 31 अक्टूबर, 1996 तककी अवधि के लिए की गई।

#### छ :- याचिकाकर्ता के विषयार

२ याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जो प्रबुख मुद्रे उठाए हैं तथा बाद में अनुरोध किए हैं, वे इस प्रकार हैं।

#### डीपिंग पर

संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और स्स डी अखबारी कागज की बड़े पैमाने पर डीपिंग के कारण अखबारी कागज उद्योग बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। अखबारी कागज की डीपिंग के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कभी से भारतीय अखबारी कागज उद्योग को क्षमिता पहुंची है।

सरकार की नीति में परिवर्तन के साथ अखबारी कागज के उत्तरी अमरीका तथा स्स के विनिर्माताओं ने अपनी कीमतों में भारी कमी की है।

उत्तरी अमरीका में अखबारी कागज का सामान्य मूल्य कनाडा में एक उत्पादक

द्वारा पुष्ट की गई कीमतों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यांचिकाकर्ता ने कनाडा और यू.एस.ए के घरेलू बाजार में अनेक नियिदास-प्रस्तुत की हैं। यांचिकाकर्ता ने दावा किया है कि य० स० स० और कनाडा के मामले में सामान्य मूल्य का लार एक समान माना जाना चाहिए और दोनों का एक ही राज्य क्षेत्र जाना चाहिए।

- यांचिकाकर्ता ने डीपिंग के अपने आरोप के समर्थन में निर्यात कीमत निर्धारित करने वेतु अनेक नियिदास-प्रस्तुत की। घरेलू बाजार में कीमतों के संबंध में नियिदास भारत को किस ग्रंथ निर्यात की कीमत लगभग एक ही समय की थी। नियिदासों में समय-अंतराल बहुत कम यांचिका सक देन है।
- उत्तरी अमरीका के उत्पादकों द्वारा अखबारी कागज की डीपिंग 250 अमरीकी डालर प्रति मीटर टन थी, स्स के मामले में यह कहा गया कि प्रांचिकारी को छुग्दी की अंतराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर स्ती उत्पादकों के लिए निर्धारित की गई उत्पादन लागत के आधार पर निकाले ग्रंथ सामान्य मूल्य पर विधार करना चाहिए।

### क्षमता पर

- घरेलू उत्पादकों द्वारा बिक्री कीमतों में कमों किस जाने के बावजूद इन देशों के आयातों को मात्रा में तेजी से दृष्टि हुई। जिसके प्रत्यरूप घरेलू उत्पादकों की बिक्री और क्षमता उपयोग बहुत कम हुआ।
- कुछेक भारतीय उत्पादकों को अखबारी कागज से उत्पादन को तो पूरी तरह से बंद करना पड़ा अध्या काफी हद तक कम करना पड़ा।
- समग्र स्पष्ट में आयात में दृष्टि होना आयात के घरेलू पेपर की तुलना में बाजार शेयर और क्षमता उपयोग में कमों होना इसी किस ग्रंथ आयातकों द्वारा हुई भारतीय उपयोग को क्षमता के प्रत्यक्ष प्रमाण है।

- ग निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टीयों के विषयार
- 
४. जिन निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टीयों ने प्राधिकारी को उत्तर भेजा था उनके द्वारा व्यक्त विषयार निम्नानुसार है;
- । ० कनाडा उप्यायोग
- डीपिंग पर
- क. यांचिकाकर्त्ता द्वारा किस गरे डीपिंग के बारे में साक्ष्य अनिश्चित तथा अस्पष्ट हैं ।
- ख. शिकायत में दिखाई देता है कि विष्व भर में लुगदी तथा बागज के उत्पाद की कीमतों में कमी हो रही है । यह तथ्य कि उत्तरी अमरीका के घरेलू बाजार में कीमतों तथा भारत को किस गरे निर्यात की कीमतों में हो रही कमी इस बात का संकेत है कि डीपिंग नहीं हो रही है ।
- ग. शिकायत में विभिन्न स्थानों में प्रयुक्त सामान्य मूल्य के बीच विसंगतियाँ हैं ।
- घ. यांचिकाकर्त्ता ने कहा है कि निर्यातक के घरेलू बाजार में प्रधानत कीमतों में समायोजनों की आवश्यकता नहीं है ।
- ঙ. यांचिका में कनाडा के बाजार में बिक्री कीमतों से संबंधित कोई जानकारी नहीं है । शिकायत में सामान्य स्प से उत्तरी अमरीका में दो स्पतंत्र देशों की बजाय उत्तरी अमरीका के एक बाजार का उल्लेख किया गया है ।

क्षीति और ऊंके कारण के बीच सम्बन्ध पर

- ক. यांचिका में यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि हुई क्षीति डीपिंग के कारण हुई है ।
- খ. कनाडा से निर्यात की कीमत ।१९७४-७५ की कीमतों से अब भी अधिन है । इस तथ्य में इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है कि विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं ने अपनी कीमतों में जनवरी, ।१९७६ के बाद से जारी कमी की है । शिकायतकर्त्ताओं को बिक्री तथा बाजार शेयर में जो नुकसान हुआ है वह डीपिंग को छोड़कर अन्य कारणों से

- ग. याचिका में इस बात का साक्षय है कि क्षति सामान्यतः अन्य कारणों से हुई हो । उदाहरण तथा पिछले वर्षों में विभिन्न आयात प्रतिबंध हटाय गये हैं । जोकि विदेशी आपूर्तिकर्ता बाजार में प्रवेश कर सके । उपचोक्ताओं का विदेशी उत्पादकों की और इकाय सामान्यतः अन्य कारणों से हुआ है जैसे गुणवत्ता, समय की पांडी, आपूर्ति की भरता आदि एक उत्पादक ने छुलाई में काम बंद कर दिया जिससे ग्राहकों को सम्भवतः आपूर्ति की समस्या हुई होगी ।
- घ. यह तथ्य कि भारत में कुछ कंपनियां जो बंद हो गई हैं वे क्षति का संकेतक हैं इसे डिग्ग से जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है । इनके बंद होने का कारण यह हो सकता है कि ये उत्पादक विदेशी सामान के अच्छे व्यापार के साथ जड़ी कर सके हैं । उपचोक्ता, विदेशी की आपूर्ति की ओर मुड़ सकता है क्योंकि वह स्थायी, दीर्घकालीन तूष्णा की गोपनीयता के बारे में प्रधिकारी का सुन सष्टट नहीं है ।
- इ. स्बीटिबी-प्राइवेट इंक
- क. भारत को निर्यात की कीमत विषय के अन्य बाजारों को किस गए निर्यात की कीमतों अथवा कारखानागत घरेलू कीमतों की तुलना में वास्तविक रूप में कम नहीं थी ।
- ख. भारत को किस गए निर्यात तथा अंतर्रिक्त बाजार में की गई बिक्री के संबंध में स्बीटीबी वैन्डलर मिल के लिए लागत तथा लाभ प्रदाता लगभग समान है तथा शेष विषय को किस गए निर्यात पर हुई लाभप्रदता की तुलना में अधिक है ।
- ग. भारत को किस गए निर्यातों तथा घरेलू बिक्री के लिए स्बीटिबी ग्रांड मिल की लागत तथा<sup>लाभप्रदता</sup> की तुलना करना कठिन है क्योंकि घरेलू बिक्री कोई हुई ही नहीं थी ।
- घ. जांच की अधिक के द्वारा न स्बीटिबी की कीमत का समायोजन ग्राहकों से प्राप्त बाजार मांग के प्रत्युत्तर में किया गया था ।
- इ. कंपनी द्वारा प्राप्त किस गए लाभप्रदक के स्तरों में कुछ उत्तर-विद्युत अलग-अलग मिल के आधार पर होगी ।

111. स्टोन कमोली डेटिड कारपोरेशन, कनाडा प्राधिकारी द्वारा निर्यात को मूलस्तुति से संबोधित नहीं किया गया था। इस यांचिका तथा प्रश्ननावली की एक प्रतीत के लिए अनुरोध किया था और इसका उत्तर भेजा था। घटकत किस गए विषयार निम्नानुसार हैं।
- क० यूरोपीय देशों में अखबारी कागज का पोत लेंदान डम्प की गई कीमतों किया गया था।
- छ० संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा अलग-अलग देश हैं और उन्हें अलग-अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।
- ग० यांचिकाकर्ता ने समृद्ध का भाड़ा तथा अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा दोनों ही 130 अमरीकी डलर प्रतीत मी० टन बलाया जो जाहीं नहीं है और बहुत ही अधिक है।
- घ० यांचिकाकर्ता ने डीपिंग के साक्ष्य के लिए सूधी कीमतों को आधार बनाया है। यह घट कीमत नहीं थी जिस कीमत पर फारोबार किया गया था।
- ड० यांचिका में विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञताएँ हैं।
- ष० यांचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि कीथिन डीपिंग के फलस्वरूप घरेलू उपयोग कोक्षीत कैसे हुई। यांचिका में कारणात्मक सम्बन्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- छ० भारत में अखबारी कागज के आयात को बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया गया था जो मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन है।
- ग० अखबारी कागज की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुईं।
- झ० अखबारी कागज के उपयोग की कीमतों में कीथिक स्प से अतार-घटाव आया है।
- ड० भारत सरकार ने अखबारी कागज पर 10% का आयात शुल्क लगाया है।
- ट० कम क्षमता उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर प्रतिद्वंद्विता करने के लिए घरेलू उपयोग की असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- ठ० भारतीय उपयोग के पास मई, १५ में आयात से नियंत्रण हटा लेने के फलस्वरूप स्टॉक का पर्याप्त भंडार था और फरवरी में भी बहुत अधिक था जब कीमतें काफी अधिक थीं।

• मैकर इंटरनेशनल कंसोर्टियम स्स [मैकर]

भारत बाजार में प्रथम अखबारी कागज की कम कीमतों पर प्रिंटा व्यक्त करते हुए निर्यातक ने भारत में अखबारी कागज के बाजार का केवल संक्षिप्त इतिहास ही दिया है।

- आयातक/उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पार्टियां
- इम्प्रेस प्र
- क० मार्ग और आपूर्ति की ताक्तों के कारण अप्रैल, १८ से सम्पूर्ण विश्व में अखबारी कागज की कीमतों में कमी आनी शुरू हुई थी।
  - छ० आयातों पर से नियंत्रण समाप्त करने के बाद भी अखबारी कागज की कीमतों में भारतीय बाजार में घृणा हुई थी।
  - ग० जांच की अवधि के दौरान अखबारी कागज की कीमतों में निरंतर कमी आई है। प्रतिमाह की गुलना में यू० स्स० कीमतों तथा आयात कीमतों के बीच स्पष्ट संबंध की पुष्टि हो जाती है।

### क्षीति पर

- १ कृष्ण अख्बारो का गज का अधिक आयात होना अन्य कारकों से जुड़ा है जैसे-  
गुणप्रत्ता, निर्मता एवं समय पर आपूर्ति;
- २ खंड याचिकाकर्ता ने न तो नुक्सान को मात्रा बताई है और न ही हुए नुक्सान  
का विस्तृत व्यौरा दिया है। सामान्य मूल्य में उतार-चढ़ाव को बजह से  
क्षीति नहीं होती है;
- ३ गंड भारतीय उद्योग ने जांच अधिकारी में भी काफी मुनाफा कमाया है;

### अन्य

- ४ कृष्ण पाटनरोधी अधिनियम के प्रावधान एवं नियम लागू नहीं होते हैं। किथि प्रावधान अधिकारों के विरुद्ध हैं, ये व्यापार एवं व्यवसाय करने के उपभोक्ताओं  
के अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं और अख्बारी का गज के उत्पादकों एवं  
उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव का बर्ताव करते हैं;
- ५ खंड उपभोक्ता उस मूल्य पर छोरोदने को कोरिश करेंगे जो मूल्य उनके उत्पादन  
लागत से कम है।

### घ. उठाए गए मुद्दों को जांच

५. निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पार्टीयों द्वारा पेश किए गए कागजातों की जांच को गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन पर विवार किया गया है और इस रिपोर्ट में  
उपयुक्त स्थलों पर उन पर कार्रवाई को गई है।

### ड. विधाराधीन उत्पाद

६. वर्तमान जांच में विधाराधीन उत्पाद अख्बारो का गज है। अख्बारो का गज एक अनकोटेड क्रिस्म का कागज है जो अख्बार छापने के लिए इर्टेमाल किया जाता है और जिसमें 65% से अधिक बजन में यांत्रिक अध्या रासायनिक-यांत्रिक प्रौद्योगिकी से प्राप्त काष्ठ रेशा के तत्त्व मौजूद रहते हैं, वे बिना आकार अध्या बहुत की कम समान आकार के होते हैं जिनके दोनों छोरों पर असमतल पार्श्व प्रॉट स्पर्ट हैं। सम पो स १ होता है जो २.५ माहको मोटर १८ माहकोन्हू से अधिक नहीं होता, और बजन में ४० ग्राम से कम तथा ६५ ग्राम से अधिक नहीं होता। अख्बारो का गज को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ की अनुसूची। के अध्याय-४८ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र के लिए बाध्यकारी नहीं है।

### घ. समान वस्तु

७. युछ हितबद्ध पार्टीयों ने तर्क दिया है कि अख्बारो का गज का आयात अधिक देशों से इसको गुणप्रत्ता जो बजह से किया गया है। लैंफिन इन हितबद्ध पार्टीयों में यह उत्पाद नहीं है कि घरेल रोग तारा उत्पादन एवं बिक्री में गए

अखिलारो कागज का तथा इन देशों से आयातित अखिलारो कागज का आदान-प्रदान कर इस्तेमाल किया गया है। इन देशों से किस ग्रंथ आयात के तरीके और घरेलू उधोग द्वारा इनकी बिक्री करने से यह बात स्पष्ट स्पष्ट से मुनिषिष्ठत हो जाती है कि संबंधित देशों से आयातित अखिलारो कागज का प्रतिस्थापन घरेलू उधोग द्वारा तकनीकी स्वं वाणिज्यिक दोनों स्पष्ट से उत्पादित स्वं बिक्री किस ग्रंथ अखिलारो कागज के लिए किया। अतः नियम २५४ के अर्थ के भौतर घरेलू उधोग द्वारा उत्पादित स्वं बिक्री किस ग्रंथ अखिलारो कागज को संबंधित देशों से आयातित अखिलारो कागज के समान-वस्तु माना जा सकता है।

#### छ. घरेलू उधोग

11. यह याचिका इंडियन न्यूजप्रेसेंट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ३आई एन एम ए, डॉ- 165, लिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली- 24 द्वारा दायर की गयी है। इसलिए याचिका घरेलू उधोग की ओर से दायर समझी जाती है।
12. एसोसिएशन ने उन घरेलू ग्रौथोर्गिक इकाईयों के बारे में सुनना भेजा है जिनका जांच अधिकारी के दौरान भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। ये इकाईयाँ नियम २५५ के अनुसार संयुक्त स्पष्ट से घरेलू उधोग का स्पष्ट लेते हैं।

#### सामान्य मूल्य

१२ धारा ७ सू। ५३० के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :

- ११। व्यापार के सामान्य क्रम में, सामान वस्तु जब निर्यातिक देश या क्षेत्र में ख्यल के उद्देश्य से हो तो उसके लिए तुलनात्मक कीमत उपधारा ३६५ के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है, या
- १२। जब निर्यातिक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान भिनता-कुलता वस्तु को बिक्री नहीं हो, या जब निर्यातिक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं हो सकती है, तब सामान्य मूल्य निर्मांकित दोनों में से एक होगा :

(क) सामान वस्तु को तुलनात्मक प्रतिनिधि कीमत जबकि इसका निर्यात निर्यातिक देश या क्षेत्र या एक उपयुक्त तोमारे देश से लिया जाता है जिसका निर्धारण उपधारा ३६५ के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है, अथवा (ख) उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की जागत तथा उसमें प्रशासनात्मक बिक्री संबंधी और सामान्य जागतों तथा जाभों के लिए उचित कीमत जोड़ी जाती है, जिसका निर्धारण उपधारा ३६५ के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है।

तेकिन प्रति दृढ़ है कि उद्गम वाले देश से भिन्न लिसो अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में जहाँ वस्तु को सिर्फ निर्यातिक देश से होकर वाहनात्मक बिक्री गया या ऐसी वस्तु निर्यातिक देश में उत्पादित नहीं की जाती है या निर्यातिक देश

में कोई तुलनात्मक कीमत नहीं है, तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जासगा ।

यह तर्क दिया गया है कि याचिका में कोई उचित साक्ष्य नहीं था और जिस बाजार पर जांच शुरू की गई है वहो वक्षित नहीं है । प्राधिकारी ने नोट किया है कि याचिकाकर्ता का यह दायित्व है कि वह प्रथम दृष्टिया मामले को स्थापित करे । याचिकाकर्ता वे साक्ष्य देने के लिए कूल संकल्प हैं जो उसके पास आसानी से उपलब्ध हैं । वर्तमान मामले में याचिका कर्ता ने इस क्षेत्र में प्रवृत्तित मूल्यों के आधार पर सामान्य कीमत के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । याचिकाकर्ता ने प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित मूल्यों के आधार पर इस क्षेत्र में प्रवृत्तित मूल्यों का साक्ष्य दिया है ये साक्ष्य मूल्य सूची के आधार पर नहीं हैं । यह सुराहनोय है कि पत्रिकाओं में प्रकाशित मूल्य कारणानागत वसूली के आधार पर नहीं हैं और इनमें समायोजन को अनुमति दो जा सकती है । तथापि, प्राधिकारी ने पाया कि प्रकाशित मूल्यों के आधार पर परीक्षित सामान्य मूल्य और कारणानागत वसूलों के आधार पर निर्यात मूल्य में पर्याप्त अन्तर है । जिसके द्वारा खर्च सामिल किए जा सकते हैं जिनके लिए निर्यातक ने घरेलू बाजार में बिक्री पर खर्च किया होगा । इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि जांच को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए उसके समक्ष सामान्य मूल्य के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टिया साक्ष्य है । निम्न छ्योरे के अनुसार प्राधिकारी ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में इन निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कनाडा के निर्यातकों द्वारा की गई वास्तविक सकल वसूली के आधार पर कनाडा के मामले में सामान्य कीमत निर्धारित की है ।

11. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने समुद्रो भाड़े तथा निर्यातक देशों में अन्तर्राष्ट्रीय भाड़े के लिए अनुचित सर्व अत्यधिक समायोजन का दावा किया है । चौंकि समुद्रो भाड़े कथा अन्तर्राष्ट्रीय भाड़े के संबंध में समायोजन निर्यातकों द्वारा दावा की गई रकम के आधार पर प्रतान किया जा रहा है इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा असंगत है ।

12. प्राधिकारी ने उपरोक्त धारा के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों को प्रश्नापत्रों भेजो ताकि उसके आधार पर सामान्य कीमत निर्णाली जा सके । जिन निर्यातकों ने सूचना भेजी है उनके मामले में सामान्य कीमत उनके द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर निर्णाली गई है और इसका छ्योरा नीचे दिया गया है :-

#### ११११ ए बो टो बो :

११११ ए बो टो बो ने यू एस ए और कनाडा में अपनी मिलों के बारे में अलग उत्तर प्रेषित किया है । निर्यातकों द्वारा दिया है कि :

१२१२ भारत को होने वाले निर्यात पर ए बो टो बो के याहूतर मिल की लाभ शर्व लाभ और गृह बाजार में बिक्री अभियान बराबर है और ऐसे विषय को किस ग्रंथ निर्यात से प्राप्त लाभ से अधिक है ।

१३१३ ए बो टो बो के ग्रांड मिल को जागत और लाभ जो तुलना भारत को होने वाले निर्यात मर लाभ आर घरेलू टक्कों से करना अधिक है, फिरों ।

धोरेलु बिक्री नहीं हुई है ,

४ ग्र० जांव अधिके दौरान स बो टी बो का मूल्य समावेश उपभोक्ता में को बाजार मांग के प्रत्युत्तर में था ।

अलग-अलग मिल के आधार पर कम्पनों द्वारा प्राप्त लाभ के स्तरों में युक्ति अन्तर होगा।

प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि निर्यातिक यह निवेदन किया है कि लागत एवं लाभ आधार पर कोई डीम्पंग नहीं हुई है। निर्यातिक का यह तर्क विधि के मुंगत प्रावधान को देखते हुए उपित नहीं है। डीम्पंग के लिए केवल निर्यातिक के घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य और भारत को होने वाले निर्यात मूल्य मुंगत है।

२६ निर्यातक का यह तर्क भी फिल-अलग-फिल के लाभ में कुछ अन्तर हो सकता है जो उपित नहीं है। सामान्य मूल्य का निर्धारण दो दाजारों में सन्दर्भित मिल को कोसतों के अनुसार करना पड़ता है। चूंकि निर्यातकों के पास क्षाड़ा और यू सम् ए में टष्ट स्प्रिंग से अलग-अलग कोसतों हैं इसलिए यू सम् ए और क्षाड़ा से फिल गए निर्यातों पर अलग से कार्रवाई करनी होगी। अतः एचीडीओ के मामलों में आगे के पैराग्राफों में क्षाड़ा और यू सम् ए के तिस सामान्य मूल्य संवं निर्यात मूल्य अलग-अलग निर्धारित फिल गए हैं।

१३। निर्यातिक ने घरेलू बाजार में अपनी बिश्रो मूल्यों के बारे में विस्तृत मुख्यालयी है। प्राप्तिकारों के अनुरोधानुसार सूचना महीना-दर-मटीना आधार पर दो गई है। धौकि निर्यातिक ने घरेलू बाजार में अपने बिश्रो मूल्य दिस हैं, इसपर सामान्य मूल्य धारा १ का ११५ से ११४ के अनुसार निर्धारित किया गया है।

४४४ एबोटोबो ने घरेलू बाजार के मूलयों में निम्नलिखित समायोजन भरने का दावा किया है :-

१४ छूट-निर्यातक ने दावा किया है कि उसने 780 अमरीकी डालर प्रति मोटन के मुधो मूल्य पर डिस्काउंट दिया है। यह डिस्काउंट दूजनवरो-मार्प, 1997 में, अमरीकी डालर था जो दूअक्टू. 1997 में बढ़कर अमरीकी डालर प्रति

मो. टन हो गया। धैर्यक निर्यातक ने घरेलू बाजार में को गई बिश्री पर छिस्काउंट दिया है, इससिंह प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजन के तिस उम्रों को अनुमति दो गई है।

४२४ अन्तर्राष्ट्रीय भाषा : निर्यातिक ने तर्क दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा जलग-जलग उपभोक्ता और पर अंतग-अंतग द्वेषा है जो दूरी परमित्यकरता है। निर्यातिक ने छर्ष हृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय भाषा को एक सुधार तक लागत का दावा किया है और उसने उर्ध्व शिख गण भारित औसत अन्तर्राष्ट्रीय भाषा लागत भी दर्शाई है। निर्यातिक द्वारा बतलाई गई भारित औसत को अनमीति दो गई है।

४५४ प्राधिकारी ने अमर दिस ग्रस पिंवरण के अंतिरिगत तारीख मिर्यारा ले उद्देश्य के तिथि इन समायोजनों जो अनुमति दी है। समायोजित मूल्यों को विवरणीकरण नागत वस्तु समझा जाया है।

स्टोन कन्सोलिएटर्स ने घरेतू मूलयों में निम्नीकृत समायोजन करते ब्रादावा किया है :-

35

- घरेलू बाजार में भण्डार गृह से उपभोक्ताओं तक अन्तर्देशीय भाड़ा,
- समानता के आधार पर मिळ से भण्डारगृह तक अन्तर्देशीय भाड़ा,
- बिश्री छपों में अन्तर,
- बैष प्रौद्योगिक्या के फारण उत्पादन लागत में अन्तर ।

**१५। छूट :** निर्यातक ने अमरीकी डालर ३५प्रैल, १९७८ से अमरीकी डालर ४अप्रैल, १९७८ प्रति मो.टन तक को छूट का दावा किया है। इस समायोजन को अनुमति मासिक आधार पर दी गई है।

**१६। अन्तर्देशीय भाड़ा :** निर्यातक ने दावा किया है कि उसने अपने भण्डार गृह से घरेलू बाजार में बिश्री को है और अपने भण्डार गृह से ग्राहकों तक भाड़े पर अमरीकी डालर ३५प्रैल, १९७८ से अमरीकी डालर ४अप्रैल, १९७८ तक छूट किया है। निर्यातक ने यह भी दावा किया है कि उसने समान आधार पर अपने संघर्ष से भण्डार गृह तक भी भाड़े पर अमरीकी डालर प्रति मो.टन का छूट किया है।

**१७। घरेलू बाजार में बिश्री के लिए अतिरिक्त बिश्री छूट होने से बिश्री छूट के लिए अमरीकी डालर प्रति मो.टन के समायोजन का दावा किया गया है।**

**१८। उत्पादन्तागतों में अन्तर के लिए** अमरीकी डालर प्रति मो.टन के समायोजन का दावा इस आधार पर किया गया है कि घरेलू बाजार में बिश्री थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करनी पड़ती है और उपभोक्ता "बिल्कुल समय पर" मुपुर्दगो चाहते हैं। निर्यातक ने तर्क किया है कि घरेलू बाजार में बिश्री के लिए उसे किसी भी उत्पादन करना पड़ता है। घरेलू बाजार में बिश्री को इस पड़ती के लिए निर्यातक पे छूट भी तर्क दिया है कि भारत को निर्यात बड़ी मात्रा में होता है और भित्ति अवधारो कागज का उत्पादन अधिक समय तक लगातार कर सकते हैं। निर्यातक का तर्क है कि बैचों में उत्पादन करने में एक मशीन की उत्पादन क्षमता जहाँ सामान्यतः  $\frac{1}{2}$  होती है, वहाँ लगातार उत्पादन में उक्त क्षमता  $\frac{1}{4}$  होगी। उससे उत्पादन में  $\frac{1}{2}$  का अन्तर होगा। अतः निर्यातक का निष्कर्ष यह है कि घरेलू बाजार में बिश्री के मामले में अतिरिक्त लागत आती है जो औपतन कैनेक्षियन डालर प्रति मो.टन की निश्चियत लागत  $\frac{1}{2}$  के आधार पर है।

**१९। उत्पादन्तागत:** अमरीकी डालर प्रति मो.टन डोगो।

निर्यातक ने यह मुनिशिष्ट करने के लिए कोई साक्षय प्रस्तुत नहीं किया है कि बैचों में तथा निरंतर उत्पादन प्रौद्योगिक्य में उत्पादन क्षमता में अन्तर होगा। इसके अलावा निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसे बैचों में उत्पादन करना पड़ा जबकि पार्टी ने दावा किया है कि उसने मात्र भण्डार गृहों से भेजा है। इसलिए निर्यातक के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है।

यद्यपि निर्यातक के दावे को पिस्तृत जारी करने की ज़रूरत है तथा प्राधिकारों ने प्रारम्भिक नियायिक कानून के प्रयोजन से **१५।** से **१६।** तक इन दावों की अनुमति दी है।

**२०। क्नाडा और यू.एस.से अन्य निर्यातक**

मैसर्स मैकार्थी टेटरौल्ट, क्नाडा ने अपने दिनांक ३ अप्रैल, १९७८ के फैसला द्वारा सुनिश्चित किया है कि उसे समय पर इन्द्रियारों के बारे में सुविधा नहीं मिली और उसने १५ अप्रैल, १९७८ तक समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया।

प्राधिकारों ने यह जोट किया है तथा नियम ६४३ के अंतर्गत प्राधिकारों नियातकों

विदेशी उत्पादकों से सूचना मंगाने के लिए नोटिस जारी कर सकता है जार यह सूचना इस नोटिस की प्रार्थना को तारीख से तोम दिनों के भीतर है। ऐसे व्यौक्तिगों को भेजनी होगी। ऐसा माना जाता है कि यह नोटिस प्रार्थकारों द्वारा अध्या निर्यातक देश के दूतावास को भेजे जाने को तारीख से एक सप्ताह के भीतर मिला जाता है। इसलिए प्रार्थकारी ने निष्पत्य किया है «मैंन्कार्थी टेटरौल्ट, कनाडा के समय को बढ़ाने के अनुरोध को मानना अनुचित होगा। तथापि, यदि सूचना भेजे गई तो प्रार्थकारों निश्चित निर्धारण के लिए उस पर विचार करेगा।

कनाडा और यू.एस.ए के अन्य उत्पादक/निर्यातक प्रार्थकारों को सूचना भेजने में असफल रहे हैं। प्रार्थकारी यह निष्पत्य किया है कि कनाडा और यू.एस.ए के अन्य निर्यातक/उत्पादक प्रार्थकारों के सहयोग देने के असफल रहे और नियम 648 के अनुसार प्रारम्भिक निष्कर्षों की घोषणा कर दो गई है। आयातकों द्वारा दो गई सूचना की जांच से पता चलता है कि जांच को अधिकारी के दौरान निम्नलिखित पार्टीयों ने भी भारत को अख्बारों कागज का निर्यात किया :

१कृ प्राइम एण्ड पोस्ट, 21-ए, नेल रोड, सिंगापुर

१छृ सबनर इंक, 1250, रेने लेवेस्क बिल्डिंग बैस्ट, कोन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा

१गृ रेशोवा फोरेस्ट प्रोडक्ट्स, कनाडा।

यूंक इन निर्यातकों ने प्रार्थकारों को सहयोग नहीं दिया, इसलिए जांच को सुरक्षात के समय परिक्रमित सामान्य भूल्य पर विचार किया गया है। यूंक इस बात का समुचित साक्ष्य है कि निर्यातकों ने घरेलू बाजार में को गई बिक्री पर भाड़े का भुगतान किया है, इसलिए 40 अमरीकी डालर प्रति छोटे टन के डिस्ट्राब से इसकी अनुमति दी गई है।

१४४ मेकर ने यह कहते हुए सूचना नहीं भेजी है कि उसके पास पृछों गयो कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थकारी ने सूचना मंगाते हुए नोटिस पर जाफ तौर पर कहा था कि निर्यातक ने यदि निम्नलिखित कोई कार्य नहीं किया है तो नोटिस को संबंधित पार्टी के पास भेज दिया जाय :-

१कृ विचाराधीन सामान का उत्पादन अध्या विनिर्माण करता है,

१छृ घरेलू बाजार में बेचता है,

१गृ भारत को निर्यात करता है,

१घृ भारत को छोड़कर अन्य देशों को नियोत करता है।

उपरोक्त को देखो हुए, मेकर जो यह प्रश्नाकारी संबंधित पार्टी प्रार्थीयों को भेजनी धूमिर थो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तथापि, मेकर ने भारतीय बाजार में प्रयत्नित कम कोमतों पर विन्ता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह कोमतों में सुधार लाने के लिए उपाय करें।

१५५ भारत में ल्सो व्यापार प्रतिनिधि परिसंघ ने जपने दिनांक 30.12.1976 के पत्र

द्वारा अनुरोध किया है कि प्रार्थकारों विदेशी आर्थिक संबंध मंत्रालय, मास्को/ल्सो को सूचना मंगाने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। तदनुसार, प्रार्थकारी ने विदेशी आर्थिक संबंध मंत्रालय, मास्को, ल्स तथा भारत में ल्सो व्यापार प्रतिनिधि परिसंघ को नोटिस जारी किया। तथापि प्रार्थकारों नोट करता है कि ल्स के लेसो भी

नियोतक/उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में कोई सूचना नहीं भेजी है। प्राधिकारी मानते हैं कि इस के नियोतकों/उत्पादकों ने प्राधिकारों को कोई सहयोग नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारों नियम 648<sup>ई</sup> के अनुसार प्रारंभिक निष्कर्षों को घोषणा करते हैं।

दूसीकोसी भी नियोतक ने उत्तर नहीं भेजा है इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का विधारण लक्ष के लिए निकाली गई उत्पादन लागत के आधार पर फिरा है। लक्ष के लिए उत्पादन लागत पहले जांच सुन करने के समय निकाली गई थी। प्राधिकारों ने लक्ष के नियोतकों/उत्पादकों से सहयोग नहीं मिलने के कारण प्रारंभिक निष्कर्ष में लिए भी सामान्य मूल्य के ऊपर परिवार फिरा है।

### स्पष्ट नियोत मूल्य

180. एबोटोबो और स्टोन कन्सोलिटेड के मामले में प्राधिकारों ने नियोतकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियोत मूल्य निकाला है। नियोत मूल्य निम्नलिखित छ्यारे के अनुसार निकाला गया है :-

**एबोटोबो :** नियोतक ने कनाडा और यू.एस.ए से किए गए अपने नियोत के पृथक छ्यारे दिए हैं। नियोतक ने बोजक तारीछ के आधार पर दोनों देशों से किए गए कारोबार-वार नियोत के जांकड़े दिए हैं। नियोतक द्वारा दिए गए महीनावार नियोत छ्यारे के आधार पर महीना-वार की आई एक नियोत मूल्य निकाला गया है। नियोतक ने निम्नलिखित समायोजन किए जाने का दावा किया है :-

### 14 - ४

**१३५ अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा :** यू.एस.ए मिल्स से किए गए नियोतों के मामले में अमरीकी डालर प्रति मो.टन की राशि का दावा किया गया है जबकि कनाडा से किए गए नियोतों के मामले में अमरीकी डालर प्रति मो.टन की राशि का दावा किया गया है।

**१३६ मुद्रो भाड़ा :** यू.एस.ए मिल्स से किए गए नियोतों के मामले में अमरीकी डालर प्रति मो.टन की राशि का दावा किया गया है जबकि कनाडा से किए गए नियोतों के मामले में अमरीकी डालर प्रति मो.टन की राशि का दावा किया गया है।

**१३७ कमोशन :** नियोतक ने दावा किया है कि उसने अमरीका से किए गए नियोतों के मामले में X को दर से छिस्काउंट दिया है और कनाडा से नियोत के मामले में X को दर से/सौदे बार दिए गए विवरण से यह पाया गया है कि नियोतक ने कनाडा से हुए नियोत के मामले में X से X के बीच कमोशन का भुगतान किया है। अधिकांश सौदों में X कमोशन दिया गया है। प्राधिकारी कमोशन के संबंध में किए गए दावे की अनुमति देना उपरित समझता है।

प्राधिकारों द्वारा उपर्युक्त मानता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजन से किए गए तक समायोजन को अनुमति दे दी जाए।

—निर्यातक ने दावा किया है कि उसने यू सस से किस ग्रंथि निर्यात के मामले में  $1\cdot625\%$  तथा कनाडा से हुए निर्यात के मामले में  $2\cdot0\%$  की दर से कमोशन का भुगतान किया है। सौदेवार छ्यौरे से पता चलता है कि निर्यातक ने कनाडा के मामले में  $1\cdot25\%$  और  $2\cdot00\%$  के बीच कमोशन का भुगतान किया है। अधिकांश लेन-देन  $2\cdot00\%$  कमोशन पर किया गया है। तथापि, कमोशन के बारे में दावे पर विचार करने की अनुमति देना उचित है। प्रारम्भिक निष्कर्षों के प्रयोजन से अन्य समायोजनों पर विचार करने की अनुमति देना उचित है।

### स्टोन कन्सोलिडेटेड :

---

४३ स्टोन कन्सोलिडेटेड ने भारत को १६ में यू सस डालर प्रति मो.टन तथा १६ तक यू सस डालर प्रति मो.टन की दर से अखबारों कागज का निर्यात किया, जबकि जांच अधीप के प्रत्येक महीने में घरेलू बाजार में निर्यातक के मूल्यों में गिरावट रही।

४४ निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उसने भारत को सभी निर्यात अपने सभी मात्र एजेंट, मैसर्स यूनोवर्सल पेपर एक्सपोर्ट कं.लि., कनाडा के जरिए किस और भारत में कोई एजेंट नहीं था। निर्यातक ने आगे और कहा है कि उसने यूनोवर्सल को कारखानागत मूल्य पर  $\times$  को दर से कमोशन दिया। निर्यातक ने भारत को किस ग्रंथि निर्यातों के माले में दिस ग्रंथि समुद्री भाड़े तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाड़े का छ्यौरा दिया है। समुद्री भाड़े के बारे में समायोजन का दावा निर्यातक द्वारा दिस ग्रंथि देय वास्तविक समुद्री भाड़े के आधार पर किया है। अन्तर्राष्ट्रीय भाड़े के संबंध में समायोजन का दावा प्रति कन्टेनर भाड़ा लागत अध्या प्रति कन्टेनर औसत भार पर आधारित है।

४५ कारखाना गत निर्यात मूल्य का परिकलन निर्यातक द्वारा की गई उपर्युक्त वृद्धि से किया गया है।

## यू स्स र तथा क्षाढा से अन्य निर्यातक तथा स्स से निर्यातक

**[१]** क्षाढा और यू स्स से अन्य उत्पादक/निर्यातक और स्स सेवकी निर्यातक/उत्पादक प्राधिकारी, को जवाब देने में असफल रहे हैं। प्राधिकारी ने यह विर्णव लिया है कि ये प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में असफल रहे हैं और प्रारंभिक जांष्य-परिणामों की घोषणा नियम ६ [४] के अनुसार कर दी गई है।

**[२]** एवनर फ्लोटा कण्ठ प्राइवेट स्टड पीस के मामले में निर्यात मूल्य का सुनिश्चय आयातकों द्वारा दी गई सूचना से किया गया है। अलग-अलग निर्यातकों के मामले में औसत ती स्टड स्टड निर्यात मूल्य में समुद्री भाड़ा, अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा तथा कमीशन का समायोजन तथा द्वारा प्रत्युत की गई सूचना के आधार पर किया गया है। पूरी निर्यातकों ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है, इसलिए तथा द्वारा किस गर्ख खर्च में से जो खर्च अधिक था उस पर विवार किया गया है।

**[३]** स्स के मामले में निर्यात मूल्य का निर्धारण वारिंगिंबक आसूचना एवं बांधियकी महानिदेशालय क्लक्टरा द्वारा संकीर्त सूचना के आधार पर किया गया है। पूरी स्स से किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया इसलिए अलग-अलग निर्यातकों के मामले में निर्यात मूल्य नहीं निकाला गया है। ती स्टड स्टड निर्यात मूल्य में समुद्री भाड़े तथा कमीशन के लिए समायोजन किया गया है। याधिकारकर्ता ने— अमरीकी डालर प्रति मी टन की दर से समुद्री भाड़े का तथा  $\times$  की दर से कमीशन का दावा

**[४]** | निर्यात किया/गया कमीशन  $\times$  और  $\times$  अधिक | इसलिए अमरीकी डालर यह प्रति मी टन की दर से भाड़े तथा  $\times$  दर से कमीशन की अनुमति देना उचित समझा है कि सर्वाधिक अमा किया गया है।

### तुलना

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार प्रावधान है।

“ठीकिंग का मार्जिन/निकालते सम्य, नामित प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और व्यापारात्मक उसी सम्य बिक्री के संबंध में की जाएगी। जो अन्तर तुलनीयता पर प्रभाव छलते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर छूट दी जाएगी; अन्तर में शामिल हैं— बिक्री की शर्तें, क्राधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, वास्तविक विवेषातर तथा वेर्ड अन्य अन्तर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित

करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है” जबकि यह तर्क कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आ रही थी इस बात को मानते हुए इसकी अच्छी प्रशंसा की जा सकती है लेकिन यहाँ तक निर्यातक द्वारा ठम्प किए जाने का संबंध है उसके बारे में यह बात<sup>असंगत है</sup>। डीम्पिंग का निर्णय करने पाला एक मात्र आवायक मुद्रदा दो विभिन्न बाजारों में निर्यातकों की मत है। हितबद्ध पार्टीयों का यह तर्क कि गिरती हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण कोई डीम्पिंग नहीं हुई थी, युक्ति संगत नहीं है। तथापि प्राधिकारी ने यह पाया है कि एबीटीबी तथा स्टोन कन्सोलिडेटेड के मामले में घरेलू बाजार में भी किमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आई। ट्रॉक ग्रूप्स और क्नाइयन बाजारों में भी कीमतें कम हो रही थीं इसलिए जांच अपेक्षित के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात की मत के औसत के आधार पर कोई तुलना गम्भीर कर सकती है। जांच प्रारम्भ करने का निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए भी प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की तुलना निर्यात की मत से माह दर माह आधार पर की थी। प्राधिकारी एबीटीबी तथा स्टोन कन्सोलिडेटेड द्वारा दी गई सूचना से यह मानता है कि सामान्य मूल्य और निर्यात की मत की तुलना माह दर माह आधार पर करना उपयित होगा। यह भी देखा गया है कि एबीटीबी और स्टोन कन्सोलिडेटेड ने भारत को किस गरे निर्यात के सभी सौदों के ब्यौरे दे दिस है। इनके आधार पर निर्यात की मत को तुलना यूस्स/क्नाइट में सामान्य मूल्य के साथ की गई है ताकि तुलना यहाँ तक संभव हो उसी समय बिन्दु के आस-पास की हो सके।

19. अन्य निर्यातकों के मामले में निर्यात मूल्य की तुलना सामान्य मूल्य के साथ इसी प्रकार से अधीत माह दर माह आधार पर की गई है।

20. इस तुलना से निम्नलिखित डीम्पिंग मार्जिन दिखाई देता है :-



५. नियंत्रित वा नाम तं.	सन पी, ई पी, ही रम।	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर			
६. क्लाइड से प्राप्त एंड पील एक्सपोर्ट	सन दी	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ई पी	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ही रम	17	32	30	42	24	51	51	51	51	51
	एन दी	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
७. यू सस ए से प्राप्त एंड पील एक्सपोर्ट	ई पी	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ही रम	56	38	38	38	38	38	38	38	38	38

# सन दी : सामान्य कीमा

ई पी : नियांत शूल

ही रम : नियांत मूल्य के प्रतिशत के लघु में हीमंग मार्किन  
ठीमंग मार्किन के बारे में यून्य संख्या यून्य आयात दर्शाता है जिसके प्रकार यह हीमंग मार्किन बन्द है

## क्षति

उक्त नियम ॥ अनुबंध-2 के अंतर्गत जब क्षति का निष्कर्ष निकाला जाता है तो सेसे निष्कर्ष में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण भी शामिल होगा । सेसा करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जासगा जिनमें शामिल हैं-ठम्प किस ग्रंथ आयातों की मात्रा, समान पस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव तथा सेसी पस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर सेसे आयातों का परिणामी "प्रभाव" कीमतों पर ठम्प किस ग्रंथ आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इसकी यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में ठम्प किस ग्रंथ आयातों द्वारा कीमतों में पर्याप्त कटौती की गई है कि क्या सेसे आयातों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में कीमतों का अन्यथा कम करना या कीमतों में होने वाली पूँछ को रोकना है जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती

नियमों का अनुबंध ॥ का नियम ॥ ॥ ॥ यह माँग करता है कि यदि एक से अधिक देशों से होने वाले उत्पाद के आयात की प्रतिपाटन जांच होती है तो नामित प्राधिकारी सेसे आयातों के प्रभाव का संघर्षी मूल्यांकन करेगा । तथापि सेसा मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब यह सुनिश्चित हो जाए कि ।

इकूँ प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में डीपिंग का मार्जिन 2% से अधिक है जो निर्धारित कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त होगा तथा प्रत्येक देश से होने वाले आयात की निर्धारित कीमत तथा मात्रा भारत में समान पस्तुओं के आयात का 3% है; और

इखूँ आयातित सामान तथा उसके पैसे ही घरेलू सामान के बीच प्रतियोगिता की जरूरी को ध्यान में रखते हुए आयात के प्रभाव का संघर्षी मूल्यांकन उपयुक्त है ।

मीजूदा मामले में, प्रत्येक निर्धारितक और साथ ही प्रत्येक देश के संबंध में डीपिंग मार्जिन दी गई सीमा से अधिक है । उसके अलावा आयात के प्रभाव का संघर्षी मूल्यांकन आयातित सामान तथा उसके पैसे ही घरेलू सामान के बीच प्रतियोगिता की जरूरी के ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है । इसलिए प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर इन आयातों के प्रभावों का संघर्षी मूल्यांकन कर सकता है ।

24. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभावों की जांच करने के लिए ऊमर नियम के अनुबंध ॥ ॥ ॥ ॥ के अनुसार प्राधिकारी ने सेसे सूचकांकों पर विचार किया जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव ढालते हैं । ऐसे उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा स्टाफ, लाभप्रदता, पूँछ बिक्री आय, डीपिंग की मात्रा तथा मार्जिन आदि का प्रभावित करते हैं ।

इकूँ:- ठम्प आयातों की मात्रा तथा बाजार हिस्ता

॥ ॥ ॥ ठम्प आयातों की मात्रा:-

भारत में अखबारों कांगज का आयात 217108 मी. ८ टन ॥ 1992-93 ॥ से बढ़कर 371967 मी. ० टन ॥ 1995-96 ॥ हो ग्रंथ और सात महीने की जांच अधिक में 382861 मी. ० टन थे संबंधित देशों से आयात सामूहिक रूप से 108330 मी. ८ टन ॥ 1992-93 ॥ से बढ़कर 228899 मी. ० टन ॥ 1995-96 ॥ हो ग्रंथ और जांच अधिक के दौरान यह 284975 मी. ० टन के थे ।

संबंधित देशों से आयात 1992-93 की तुलना में जौर्य अवधि में निरपेक्ष स्प्रे से 35% तक बढ़े जैसाकि पित्र -1 से देखा जा सकता है। देश के कुल आयातों में संबंधित देशों का हिस्सा 50% [1992-93] से बढ़कर 74% [जौर्य अवधि में] हो गया। भारत में अखबारी कागज की कुल मांग में संबंधित देशों का बाजार हिस्सा 21% [1992-93] से बढ़कर 32% [1995-96] और जौर्य अवधि में 54% हो गया जैसा कि पित्र -2 से देखा जा सकता है।

#### छ. घरेलू उद्योग की प्रभावित करने वाले कारक

##### ॥।॥ उत्पादन तथा क्षमता उपयोग

घरेलू उद्योग का उत्पादन 1992-93 और 1995-96 के बीच 2.80 लाख और 2.90 लाख के बीच रहा। जौर्य अवधि में उत्पादन में 12% तक वृद्धि हुई तथापि यह पाया गया है कि टी स्न पी स्ल की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है [50,000मी टन की घरेलू उद्योग ने 47% [1992-93] से 40% [1995-96] तक बाजार हिस्सा छोया। तथापि जौर्य अवधि में बाजार हिस्सा तेजी से गिर कर 17% रह गया जैसा कि पित्र -3 से देखा जा सकता है। यारिकार्का ने सुधना दी है कि ऐसर्स नेपा लिं, एनालक्ष्मी पेपर मिल्स लिं तथा औरेशाबाद पेपर मिल्स लिं ने डीम्पग की पद्धति से रखते हुए उत्पादन बंद कर दिया है।

##### ॥॥॥ सम्पूर्ण मात्रा में बिक्री :

सम्पूर्ण मात्रा में घरेलू उद्योग की बिक्री 1992-93 और 1995-96 के बीच 2.70 लाख मी। टन और 2.95 लाख मी। टन के बीच रही। तथापि बिक्री जौर्य अवधि में पार्श्वक आधार पर 45% तक तेजी से गिरी जैसा कि ऊर के पित्र से देखा जा सकता है।

##### ॥॥॥ बिक्री की मत प्रवृत्ति

घरेलू उद्योग संबंधित देशों से सत्ते आयातों के कारण अपने उत्पाद को बेचने में सफल नहीं हुआ। उपभोक्ताओं ने अन्य स्रोतों से उपलब्ध सत्तें उत्पाद की वजद से कम की मतों और अधिक छूट की मांग की। जौर्य अवधि में नियर्तक द्वारा लगातार कम की मतों की पेशकाने घरेलू उद्योग की अधिक छूट देने के लिए मजबूर किया, जिनके परिणामस्पृष्ठ भारतीय बाजार में की मतों को कम करना पड़ा। यह भी नोट किया गया कि जौर्य अवधि के दौरान प्रमुख कम्पनी सामग्री यात्रा मूल्यों में भी गिरावट आई। तथापि यह देखा जा सकता है कि जौर्य अवधि के दौरान उत्पादन लागत में गिरावट की तुलना में बिक्री की मते औरी रही।

॥।॥ स्टॉक : --- घरेलू उद्योग के महीने के अंत के स्टॉक जौर्य अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रपृति का संकेत करते हैं जैसा कि पित्र से देखा जा सकता है। नेपा के पास अखबारी कागज के बिक्री योग्य स्टॉक मौजूद थे। कम्पनी द्वारा काम्बन्दी नियर्तक के लिए भारत में कस्तुर डम्प करने का कोई कारण नहीं हो सकता।

## ॥/॥ लाभहानि

घरेलू उद्योग जौषं अवधि से पहले लाभ कमा रहा था । तथापि, घरेलू उद्योग को जौषं अवधि के दौरान उत्पादन लागत और उपित लाभों से कम कीमतों पर अख्बारी कागज की बिक्री से वित्तीय हानियाँ हुई हैं ।

**क्षति का निष्कर्षः**— उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचा है कि:

॥।॥ सबैधित देशों से आयात निरपेक्ष रूप से बढ़े हैं;

॥।॥ उत्तरपर्ती महीनों में दी जाने वाली डिल्लीपरी के लिए लगातार कम दरों पर अख्बारी कागज की आपूर्ति के लिए निर्यातकों ने समझौते किए । इससे भारतीय उपभोगता को अपनी कीमतों उत्पादन लागत तथा उपित लाभ से काफी कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

॥।॥। सबैकट देशों से आयातों के परिणामस्वरूप भारतीय बाजारों में कीमतों में कमी हुई ।

॥।॥। घरेलू उद्योग को बिक्री जौषं अवधि के दौरान लेजी से निर्गत ।

॥।॥। घरेलू उद्योग के पास अख्बारी कागज के स्टॉक जौषं अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं ।

उपर्युक्त प्रकार यह देखा गया है कि सबैकट देशों से होने वाले आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

## कारणात्मक संबंध

उपर्युक्त आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को आर्थिक हानि हुई या नहीं, इसका निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने निम्नानीकृत तथ्यों को ध्यान में रखा:

॥।॥ सम्बद्ध देशों से इस उत्पाद के आयात में समग्र रूप से तथा भारत में इस उत्पाद के उत्पादन और खपत के संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । सकल उत्पाद में सम्बद्ध देशों के शेयर में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । इसके सीधे परिणाम के रूप में घरेलू उद्योग के बाजार स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट आई ।

॥।॥। सम्बद्ध देशों से अख्बारी कागज के उपर्युक्त गर मूल्य पर वास्तविक आयात ने घरेलू उद्योग को अपने विक्र्य मूल्य को अलाभकारी स्तर तक कम करने के लिए बाध्य किया है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में कीमत को कम करने की स्थिति बन गयी है । उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ ।

इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति सम्बद्ध देशों से उपर्युक्त गर आयात के कारण हुई ।

## ॥२॥ भारतीय उपयोग का हित और अन्य मुद्दे

सामान्य स्तर से प्रतिपाठन शुल्कों का उद्देश्य से पाठन को समाप्त करना है जो घरेलू उपयोग को छोटी पहुँचा रहा है तथा भारतीय बाजार में बुली और बिना ऐदशाव की प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति को पुनः बदल करना है जोकि देश के सामान्य हित में है।

यह माना जाता है कि प्रतिपाठन शुल्क लगाने से अखबारी कागज से विनिर्मित उत्पादों की कीमत के स्तर प्रभावित हो सकते हैं और तद्वपरान्त इन उत्पादों की सुलनात्मक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर छुछ प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु प्रतिपाठन उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होमी विशेषकर तब जब कि प्रतिपाठन शुल्क को उस राशि तक सीमित रखा जाए जो घरेलू उपयोग की क्षमता की पूरी करने के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत, प्रतिपाठन उपायों को लागू करने से पाठन क्रिया द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जास्ते, यह घरेलू उपयोग की अवनति को रोकेगा और उपक्रोक्ताओं को ज्यादा विस्तृत पर्याय की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करेगा। प्राधिकारी ने नोट किया है कि प्रतिपाठन उपायों से किसी भी तरह से सम्बद्ध देशों से होने वाले आयातों पर प्रतिक्रिया नहीं लगेगा, इसलिए उपक्रोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

घरेलू उपयोग की क्षमता को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिपाठन शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी को घरेलू उपयोग की उत्पादन लागत तथा घरेलू उपयोग के लिए उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए घरेलू उपयोग के लिए भारत में संबद्ध उत्प्रेरक यदों के उपयोग बिक्री मूल्य पर निर्भर रहना पड़ा।

भारत सरकार द्वारा लगाया गया आयात शुल्क घरेलू उपयोग द्वारा उठाई गई हाईन की मात्रा के निर्धारण के लिए संगत है और तदनुसार इसको ध्यान में रखा गया है।

यह अनुभव किया गया है कि अखबारी कागज उपयोग आवर्ती किस्म का है और सम्य-सम्य पर इसको उतार-पढ़ाव होता रहता है। किन्तु जैसा कि ऊपर बुलना के अन्तर्गत बताया गया है पाठन का निर्धारण सामान्य मूल्य और लगभग एक ही सम्य में किस गए निर्धारित के मूल्य के संदर्भ में किया जाता है। इसलिए उपयोग का आवर्ती स्थर्म पाठन के निर्धारण के लिए असंगत है।

32. जहाँ तक सक पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि गोपनीयता संबंधी नियमों में यह दिया गया है कि यदि प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध का कोई औपचित्य नहीं है अथवा सूचना देने वाला या तो उक्त सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता या उसे सामान्य स्तर से उजागर करने का अधिकार नहीं संपन्ना चाहता तो वह इस प्रकार की सूचना को रद्द कर सकता है। निर्यातिक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली में में टाइप की गलती है और "रिगार्ड" शब्द के स्थान पर "दिसरिगार्ड" रखा जाए।

#### ट० निष्कर्ष

33. पूर्वोक्त पर विवार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि:
- क० यू स्स ए, कनाडा और स्स मूल के या वहाँ से निर्यातित अखबारी कागज का भारत को निर्यात इसकी सामान्य कीमत से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;
  - ख० इन देशों से अखबारी कागज के आयात से घरेलू उपयोग को आर्थिक क्षीति हुई है।
  - ग० सम्बद्ध देशों से आयात के कारण क्षीति हुई है।

घरेलू उपयोग को आर्थिक क्षीति को समाप्त करने के लिए जांच परिणाम के लम्बित रहने तक, सम्बद्ध देशों के या वहाँ से निर्यात किए गए अखबारी कागज के सभी आयात पर अनित्तम जांच परिणाम आने तक, अननित्तम स्तर से प्रतिपाटन शुल्क लगाना आवश्यक समझा गया है।

इस बात पर विवार किया गया कि डीम्पिंग मार्जिन से कम शुल्क लगाना हाँचियों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। इस उद्देश्य से प्रत्येक निर्यातिक के लिए आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उपयोग की ऊ उपित बिक्री कीमत से की गई जिसका निर्धारण जांच-अधिकारी के लिए किया गया है। जहाँ यह अन्तर डीम्पिंग मार्जिन से कम था, वहाँ डीम्पिंग मार्जिन से कम शुल्क की अनुशंसा की गई। तदनुसार प्राधिकारी यह तिफ्टरिश करता है कि अनित्तम निर्धारण के लम्बित रहने तक इन देशों के या इन देशों से निर्यात किए गए, सीमा शुल्क टैरिफ के अन्याय 48 के अन्तर्गत आने वाले अखबारी कागज के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की

तिथि से वे अनन्तम् शूलक लगाए जाएं जो कि नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं :

निम्नलिखित मूल के या वहाँ के निर्धारित उत्पाद	निर्धारितक का नाम	शूलक को राखि ₹ लौ प्रति मो० टन॥
--	-------------------	------------------------------------

1. यू.एस.ए.	क० शबोटीबो प्राइस इंक, छ० प्राइस एण्ड पीस ग० उपर्युक्त से भिन्न निर्धारितक	6250 2513 6250
-------------	--	----------------------

2. क्नाडा	क० शबोटीबो प्राइस इंक क० स्टोन कंसोलिडेट कारपोरेशन, छ० देशावा फोरेस्ट प्रोडक्ट्स ग० प्राइस एण्ड पीस घ० उपर्युक्त से भिन्न निर्धारितक	3089 1041 2692 5160 5160
-----------	--	--------------------------------------

3. लौ	कोई भी निर्धारितक	319।
-------	-------------------	------

36. प्राधिकारी द्वारा ज्ञात आयातकों, निर्धारितकों, वाचिकाकर्ताओं तथा अन्य दित-बद्ध पक्षों से अलग से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस पत्र के जारी होने को तारीख से 40 दिन के भीतर अपने विवार भेज दें। अन्य कोई इच्छुक पार्टी भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर अपने विवार भेज सकते हैं।

**MINISTRY OF COMMERCE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 1997

**Subject :** Anti dumping investigation concerning imports of newsprint from USA, Canada and Russia - Preliminary Findings

**No. 21/ADD/96:**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

**A. PROCEDURE**

1. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
  - a. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received written petition from Indian Newsprint Manufacturers Association alleging dumping of newsprint originating in or exported from the USA, Canada and Russia;
  - b. The preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were pointed out to the petitioners;
  - c. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, decided to initiate investigations against alleged dumped imports originating in or exported from the USA, Canada and Russia (hereinafter referred to as the subject countries). The Authority notified the Embassies of the subject countries about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules;
  - d. The Authority issued a public notice dated 20-12-1996, published in the Gazette of India, extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of newsprint, classified under chapter 48 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from USA, Canada and Russia;
  - e. The Authority forwarded copy of the public notice to the known exporters (whose details were made available by the petitioner) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing, within forty days, in accordance with the rule 6(2);

- f. The Authority forwarded copies of the public notice to the known importers of newsprint in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;
- g. Request was also made to the Central Board of Excise & Customs (CBEC) to arrange copies of all the relevant Bills of Entries for the period of investigation. No information has, however, been received from the CBEC;
- h. The Authority provided copies of the petition to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with rule 6(3) supra;
- i. The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information to the following exporters:
  - Abitibi Price Inc., Canada,
  - Abitibi Price Sales Corp., USA,
  - Bowater Mersey Paper Co. Ltd., Canada,
  - Soucy Champion Inc., Canada,
  - Daishowa Forest Products Ltd., Canada,
  - Stora Forest Industries Ltd., Canada,
  - Skytyvkar Forest Complex, Russia,
  - Kondopoga Pulp & Paper Combinat, Russia,
  - Soll Kamsk Pulp & Paper Combine, Russia,
  - Balakhna Pulp & Paper Combine, Russia,

The following exporters filed response to the questionnaire within the extended time:

- Abitibi-Price Inc. (hereinafter referred as Abitibi);
- Stone Consolidated Corp., USA (hereinafter referred as Stone Consolidated).
- j. A number of exporters, importers and consumers requested for extension of time, which was allowed by the Authority till 28.2.1997;
- k. The Embassies of USA, Canada and Russia in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and exporter's questionnaire was sent to the Embassies also alongwith a list of known exporters/producers;

- I. The questionnaire was sent to the known Indenting agents and importers of newsprint in India, calling for necessary information in accordance with rule 6(4);
- m. A number of importers/ consumers of newsprint in India requested for copies of the Initiation notification, questionnaire and/or extension of time for filing response. The extension of time was allowed upto 28th Feb., 1997. The Authority, however, holds that there is no provision for obtaining or waiting for responses from all the interested parties or giving any additional time to those interested parties from whom the Authority had not called for information in the first instance.
- n. Information regarding the domestic industry was sought from the petitioners. The petitioners furnished information in respect of the following:
  - Mysore Paper Mills Ltd. (MPM),
  - Nepa Ltd (Nepa),,
  - Tamil Nadu Newsprint and Paper Ltd. (TNPL),
  - Hindustan Newsprint Ltd. (HNL).
- o. Information deemed necessary for the purpose of preliminary findings was verified by the Authority;
- p. Cost investigations were also conducted for the purpose of preliminary findings to work out optimum cost of production and cost to make and sell newsprint in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner so as to ascertain if anti dumping duty lower than the dumping margin would be enough to remove injury to the domestic industry;
- q. The investigation was carried out for the period starting from 1st April, 1996 to 31st Oct., 1996;

## B. **PETITIONERS' VIEWS**

2. The petitioners have raised the following major issues in their petition and in their subsequent submissions:

### **On dumping:**

- The newsprint industry is passing through an unprecedented crisis due to large scale dumping of newsprint from USA, Canada and Russia;
- The dumping of newsprint coupled with the fall in the international prices has injured the Indian newsprint industry;

- With the changes in the Government policies, the North American and Russian manufacturers of newsprint reduced their prices drastically;
- The normal value of newsprint in the North America is established by the prices confirmed by a producer in Canada. The petitioner furnished a number of quotations in the domestic market of Canada and USA. The petitioner claimed that the same level of normal value should be considered in case of USA and Canada and the two may be considered as a territory.
- The petitioner furnished a number of quotations to establish export price in support of its allegation of dumping. The quotations with regard to prices in the domestic market and export price to India were at nearly the same point of time (the time lag in the quotations is as low as one day);
- There is dumping of newsprint by the North American producers to an extent of US \$ 250 per MT;
- In case of Russia it was submitted that the Authority should consider the normal value based on cost of production constructed for Russian producers, on the basis of international prices of Pulp;

On injury :

- In spite of reduction in the selling prices by the domestic producers, there was a sharp increase in the quantum of imports from these countries, resulting in very poor sales and capacity utilisation of the domestic producers;
- Some of the Indian producers have been forced to completely stop or significantly curtail production of newsprint;
- The increase in imports in absolute terms, market share of imports vis-à-vis domestic share, and the fall in the capacity utilisation are a direct consequence of injury to the Indian industry caused by the dumped imports.

**C. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

3. The views expressed by exporter, importers and other interested parties, who have responded to the Authority, are as under:

I. Canadian High Commission:

I) On dumping:

- a) The evidence of dumping provided by the petitioner is uncertain and not clear.

- b) The complaint shows that, world-wide, the prices for pulp and paper products are declining. The fact that prices in the North American domestic market and exports to India are declining is an indication that dumping may not be occurring.
- c) There are discrepancies between the normal value used in various places in the complaint.
- d) The petitioner has assumed that the prices prevailing in the exporters' domestic market do not warrant adjustments.
- e) There is no information in the petition relating to selling prices in the Canadian market. The complaint generally refers to a North American market, rather than the two independent countries in North America.

II) On injury and causal link :

- a) There is little evidence in the petition to show that the injury suffered is being caused by dumping.
- b) The export prices from Canada are still higher than prices in 1994-95. This fact does not support the allegation that the foreign suppliers drastically reduced their prices after Jan., 1996. The complainants have lost sales and market share for reasons other than dumping.
- c) There is evidence in the petition that injury may have been caused by other factors. For instance, various import restrictions were lifted over the years, enabling the foreign suppliers to enter the market. The consumers may have shifted to foreign producers for other reasons, such as quality, timeliness, dependability of supply. One producer had its annual shut down in July, which might have caused supply problem for customers.
- d) The fact that some companies in India have closed is an indicator of injury, not necessarily linked to dumping. The closure could be inability of these producers to compete with fairly traded foreign goods. The consumers might have moved to foreign supply as the same were stable, long-term source.
- e) The standing of the Authority with regard to confidentiality of information is not clear.

II. Abitibi-Price Inc.:

- a) The export price to India were not materially lower than the range of domestic ex-works prices or export price to other world markets;
- b) The cost and profitability for Abitibi's Chandler Mill regarding exports to India and sales in the home market are nearly identical and higher than profitability on exports to rest of the world;

- c) The cost and profitability for Abitibi's Grand Mill are difficult to be compared for exports to India and domestic sales, as there were no domestic sales;
- d) Abitibi's price adjustments during the investigation period were in response to market demand from the customers;
- e) There will be some variations in the profitability levels achieved by the company on mill by mill basis.

III. Stone Consolidated Corp., Canada: The exporter was not originally addressed by the Authority. It requested for a copy of the petition and questionnaire and filed its response. The views expressed are:

- a) Newsprint has been shipped from European countries at dumped prices;
- b) USA and Canada are separate countries and should be treated separately;
- c) The petitioner has indicated ocean freight and inland freight both as US \$ 130 per MT, which is incorrect and extremely high;
- d) The petitioner has based evidence of dumping on list prices, which is not the price at which the business is transacted;
- e) There are various contradictions in the petition.
- f) The petitioner has not brought out how the domestic industry has suffered injury as a result of alleged dumping. There is no reference to causal link in the petition;
- g) Imports of newsprint in India were largely controlled and were subjected to quantitative restrictions;
- h) The prices of newsprint declined in the international market;
- i) The newsprint industry has cyclical rise and fall in the prices;
- j) The Government of India has imposed 10% import duty on newsprint;
- k) The low capacity utilisation is a direct consequence of inability of the domestic industry to compete on the basis of international prices;
- l) The Indian industry was holding high level of stock subsequent to decontrol of imports in May, '95 and even in Feb., '96, when the prices were very high.

**IV. Mekor International Consortium, Russia (Mekor):** While expressing concern at the lower prices of newsprint prevailing in the Indian market, the exporter has given only a brief history of newsprint market in India.

**V. Importers/Consumers/Other interested parties:**

i) On dumping:

a) The prices of newsprint started declining world-wide from April, '96 due to forces of demand and supply;

b) Even after decontrol of imports, prices of newsprint increased in the Indian market;

c) The prices of newsprint during the investigation period declined continuously. A month-by-month comparison clearly establishes link between the US prices with the import prices;

ii) On injury:

a) Increased imports of newsprint are related to other factors, such as quality, dependability and timely supply;

b) The petitioner has neither quantified injury nor presented any descriptive account of the injury suffered. Normal price variations do not tantamount to injury;

c) The Indian industry has made healthy profits even in the investigation period;

iii) Others

a) Provisions of the Anti-dumping Act and Rules do not apply. The said provisions are ultra-vires, imposes restrictions on the right of the consumers to carry on trade and business and discriminates between the newsprint producers and consumers;

b) The consumers would try to purchase at prices which would lower their production costs;

#### **D. EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED**

4. The submissions made by the exporters, importers, petitioner, consumers and other interested parties have been examined and considered and have been dealt at appropriate places in this notification.

#### **E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION & SCOPE OF INVESTIGATION**

5. The product considered in the present investigation is newsprint. Newsprint is an uncoated paper of a kind used for printing of newspaper, of which not less than 65% by weight of the total fiber

content consists of wood fiber obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surf (1 Mpa) on each side exceeding 2.5 micro meter (micron), weighing not less than 40 gsm and not more than 65 gsm. Newsprint is classified under chapter 48 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

#### F. LIKE ARTICLES

6. Some of the interested parties have argued that the newsprint has been imported from the said countries on account of its better quality. It is, however, not disputed by these interested parties that the newsprint produced and sold by the domestic industry and imported from these countries have been used interchangeably. The pattern of imports from these countries and sales by the domestic industry clearly establish that the newsprint imported from the subject countries substituted newsprint produced and sold by the domestic industry -- both technically and commercially. The newsprint produced and sold by the domestic industry is, therefore, considered as like article to the newsprint imported from the subject countries within the meaning of the rule 2(d).

4

#### G. DOMESTIC INDUSTRY

7. The petition has been filed by Indian Newsprint Manufacturers Association (INMA), D-165, Defence Colony, New Delhi-110024. The petition is, therefore, considered as having being made on behalf of the domestic industry.
8. The Association has furnished information with regard to the domestic industry in respect of units which account for a major proportion of the total domestic production of newsprint in India during the investigation period. These units collectively constitute domestic industry in accordance with Rule 2(b) supra.

#### H. NORMAL VALUE

9. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:
  - (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
  - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the

sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

10. Argument has been raised that there was no proper evidence in the petition and the very basis on which the investigations were initiated was not proper. The Authority observes that the onus on the petitioner is to establish a *prima facie* case. The petitioner is obliged to furnish evidence as is reasonably available to it. In the instant case, the petitioner furnished evidence of normal value on the basis of prices prevailing in the territory. The petitioner has furnished evidence of the prices prevailing in the territory on the basis of prices published in a leading journal. The same are not on the basis of list prices. It is appreciated that the prices published in the journal need not be ex-works realisations and may warrant adjustments. However, the Authority found that the differences in the normal values calculated on the basis of the published prices and export prices on the basis of ex-works realisations were significant enough to take into account expenses which the exporters may have to incur on sales in home market. The Authority, therefore, holds that there was sufficient *prima facie* evidence before the Authority with regard to normal value to justify investigations. The Authority has determined for the purpose of these preliminary findings, as detailed hereinbelow, normal value in case of Canada based on the actual net realisations by the exporters from Canada on the basis of the information furnished by these exporters.
11. Argument has been raised that the petitioner has claimed incorrect and extremely high adjustment on account of ocean freight and inland freight in the exporting country(ies). Since the adjustment with regard to ocean and inland freight are being allowed on the basis of

amounts claimed by the exporters, the amounts claimed by the petitioner are irrelevant.

12. The Authority sent questionnaire to the exporters to furnish information in accordance with the section cited above so that the normal value could be worked out. The normal value in case of those exporters who have furnished information has been worked out on the basis of information furnished by them and the same is explained hereinbelow:

(I) Abitibi:

I) Abitibi filed separate response in respect of its Mills in USA and Canada. The exporter argued that:

- a) The cost and profitability for Abitibi's Chandler Mill on exports to India and sales in the home market are nearly identical and higher than profitability on exports to rest of the world;
- b) The cost and profitability for Abitibi's Grand Mill are difficult to be compared for exports to India and domestic sales, as there were no domestic sales;
- c) Abitibi's price adjustments during the investigation period were in response to market demand from the customers;
- e) There will be some variations in the profitability levels achieved by the company on mill by mill basis.

The Authority observes that the exporter has pleaded no dumping on the grounds of cost and profitability. The argument of the exporter is not tenable in view of the relevant provision of law. For dumping, only the normal value in the exporter's domestic market and the export price to India are relevant.

II) The argument of the exporter that there may be some variations in the Mill by Mill profitability is also not tenable. The normal value has to be determined in accordance with the prices of the Mill in question in the two markets. Since the exporter has distinctly separate pricing in Canada and USA, the exports made from USA and Canada have to be treated separately. Therefore, in case of Abitibi, Normal values and export prices have been determined separately for Canada and USA in the following paragraphs.

III) The exporter has furnished detailed information with regard to its selling prices in the domestic market. The information has been furnished on month to month basis, as requested by the Authority. Since the exporter has furnished its selling prices in the domestic market, the normal value has been arrived at in accordance with Section 9A(1)c(i).

iv) Abitibi has been claimed the following adjustments in the prices in the domestic market:

a) Discounts: The exporter has claimed that it had paid discounts on the list price of US \$ 780 per MT. The discounts increased from US \$ \*\*\* (Jan-Mar., 1996) to US \$ \*\*\* per MT (Oct., 1996). Since the exporter has allowed discounts on sales made in the domestic market, the same have been allowed for the purpose of preliminary determination.

b) Inland freight: The exporter has argued that the inland freight varies from customer to customer, depending upon the distance involved. The exporter has claimed a range of inland freight cost incurred, instead of a single value. The Authority observes that the rules governing comparison requires due allowance to be given for all factors which affect price comparability. The exporter should have claimed adjustment on the basis of average inland freight cost incurred by it. Since the exporter has not claimed average freight, the same has been allowed on the basis of lowest freight cost incurred.

v) The Authority has allowed these adjustments for the purpose of preliminary determination, except as detailed in the foregoing. The adjusted prices have been considered as net ex-works realisations.

(II) Stone Consolidated: Stone Consolidated has claimed the following adjustments in the domestic prices:

- Discounts,
- Inland freight from warehouse to customers in domestic market;
- Inland freight from mill to warehouse on equalised basis.
- Difference in selling expenses;
- Difference in production costs because of batch process.

The basis of claiming adjustments on account of above are as under:

a) Discounts: The exporter has claimed discount ranging between US \$ \*\*\* (April, 1996) to US \$ \*\*\* (Oct., 1996) per MT. This adjustment has been allowed on monthly basis.

b) Inland freight: The exporter has claimed that it has sold in the domestic market from its warehouses and has incurred an expenditure of US \$ \*\*\* (April, 1996) to US \$ \*\*\* (Oct., 1996) on freight from its warehouses to customers. The exporter has further claimed that it has incurred an expenditure of US \$ \*\*\* per MT on freight from its plant to warehouses, on equalised basis.

c) An adjustment of US \$ \*\*\* per MT on account of selling expenses has been claimed, being the additional selling expenses on account of sales to the domestic market.

d) An adjustment of US \*\*\* per MT on account of difference in product costs has been claimed on the ground that the sales in the home market are of smaller lots and the customers take "just-in-time" deliveries. The exporter has argued that it has to produce in batches for sales in the home market. Contrary to this system of sales in the home market, the exporter has further argued that exports to India are in large volume and the mills can produce newsprint continuously for much longer duration. The exporter has argued that a machine which normally operates at \*\*\*% efficiency in batch production would operate at \*\*\*% efficiency in continuous production, resulting in a difference of \*\*\*% in production. The exporter has, therefore, concluded that there is an additional cost involved in case of sales in the home market, which has been estimated to as US \$ \*\*\* per MT, considering average fixed cost of C\$ \*\*\* per MT.

The exporter has not furnished any evidence to establish that there will be a difference in efficiency in batch and continuous production process. Moreover, it is also not clear from the documents submitted by the exporter that it has to produce in batches when the party has claimed that it has despatched goods from warehouses. The claim of the exporter is, therefore, not accepted.

Though the above contentions of the exporter requires detailed verification, the Authority has allowed claims at (a) to (c) for the purpose of preliminary determination.

(III) Other exporters from Canada and USA:

M/s. McCarthy Tetrault, Canada replied vide fax dated 3rd April, 1997 that it did not receive the enquiry in time and requested for extension upto 15th April, 1997.

The Authority observes that under Rule 6(4), the Authority may issue a notice calling for information from the exporters, foreign producers and such information shall be furnished by such persons within thirty days from the date of receipt of the notice. The notice is deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the Embassy of the exporting country. The Authority, therefore, holds that it would have been inappropriate to grant extension of time requested by McCarthy Tetrault, Canada. The Authority would, however, consider the response, if furnished, for definitive determination.

The other producers/exporters from Canada and USA have failed to respond to the Authority. The Authority holds that the other exporters/producers from Canada and USA failed to co-operate with the Authority and the preliminary findings have been announced in accordance with Rule 6(8).

Scrutiny of the information furnished by the importers reveals that the following parties have also exported newsprint to India during the investigation period.

- a) Price & Piece, 21-A, Neil Road, Singapore;
- b) Avenir Inc., 1250, Rene-Levesque Blvd West, Montreal, Quebec, Canada;
- c) Dalshawa Forest Products, Canada.

Since these exporters have not co-operated with the Authority, the normal values considered at the time of initiation have been considered. Since there is reasonable evidence that the exporters have paid freight on sales made in home market, an adjustment on account of the same has been allowed at US \$ 40 per MT.

- (IV) Mekor has not furnished information requested, stating that it had no information on the questions raised. The Authority had clearly stated in the notice calling for information that in case the exporter did not undertake any of the following activities, the notice may be passed on to the party concerned:
- a. produces or manufactures the goods under consideration,
  - b. sells in the domestic market,
  - c. exports to India,
  - d. exports to countries other than India.

In view of the above, Mekor should have transmitted the questionnaire to the concerned party(ies). This was not done by Mekor.

Mekor has, however, expressed concern at the lower prices prevailing in the Indian market and has requested that Government of India should take measures to improve the same.

- (V) The Trade Representation of Russian Federation in India requested vide letter dated 30.12.1996 that the Authority may issue notice calling for information to the Ministry of Foreign Economic Relations, Moscow, Russia. The Authority accordingly issued notice to the Ministry of Foreign Economic Relations, Moscow, Russia as also to the Trade Representation of Russian Federation in India. The Authority however, notes that none of the exporters/producers from Russia has furnished information in the prescribed format. The Authority holds that the exporters/producers from Russia have failed to co-operate with the Authority and preliminary findings are being announced in accordance with Rule 6(8). Since none of the exporters has responded, the Authority has determined normal value on the basis of cost of production constructed for Russia. The cost of production was earlier constructed for Russia at the time of initiation. The Authority has considered the same level of normal value for preliminary

determination also in view of non-co-operation from the exporters/producers from Russia.

### I. EXPORT PRICE

13. In case of Abitibi and Stone Consolidated, the Authority has determined the export price on the basis of submissions made by the exporters. The export price has been arrived at as detailed hereinbelow:

14. Abitibi:

The exporter has furnished separate details of exports made by it from Canada and USA. The exporter has furnished transaction-wise details of exports made from the two countries, on the basis of invoice dates. The month-wise CIF export price has been worked out on the basis of details of month-wise exports furnished by the exporter. The exporter has claimed the following adjustments:

a) Inland freight : An amount of US \$ \*\*\* per MT has been claimed in case of exports made from US mills, whereas an amount of US \$ \*\*\* per MT has been claimed in case of exports made from Canada;

b) Ocean freight: An amount of US \$ \*\*\* per MT has been claimed in case of exports made from US mills, whereas an amount of US \$ \*\*\* per MT has been claimed in case of exports made from Canada;

c) Commissions: The exporter has claimed that it has paid discount @ \*\*\*% in case of exports from US and @ \*\*\*% in case of exports from Canada. It is found from the transaction wise details that the exporter has paid commissions ranging between \*\*\*% and \*\*\*% in case of exports from Canada. Majority of transactions are with \*\*\*% commission. The Authority considers it appropriate to allow the claim with regard to commission.

The Authority considers it appropriate to allow the adjustments from (a) to (c) for the purpose of preliminary findings.

15. Stone Consolidated:

a) Stone Consolidated has exported newsprint to India at US \$ \*\*\* per MT in \*\*\*, 1996 and at US \$ \*\*\* per MT from \*\*\*\*, 1996, whereas the prices of the exporter in the domestic market declined in each month of the investigation period.

b) The exporter has stated that it has made all exports to India through their sole agents, Universal Paper and there was no agent in India. The exporter has further stated that it paid commission to Universal Paper @ \*\*\*% on ex-works price. The exporter has furnished details of ocean freight and inland freight paid by it on exports to India. Adjustment with regard to ocean freight has been claimed on the basis

of actual ocean freight payable/paid by the exporter. Adjustment with regard to inland freight is based on freight cost per container and average load per container.

- c) The ex-works export price has been worked out from the above information given by the exporter.

**16. Other exporters from USA and Canada and exporters from Russia:**

- a) The other producers/exporters from Canada and USA and all the exporters/producers from Russia have failed to respond to the Authority. The Authority holds that these exporters have failed to co-operate with the Authority and the preliminary determination have been announced in accordance with Rule 6(8).
- b) The export price in case of Aenor, Daishowa and Price and Piece has been determined from the information given by the importers. The average C&F export price in case of individual exporters has been adjusted for ocean freight, inland freight and commission, on the basis of information furnished by \*\*\* and \*\*. Since the exporters have not co-operated with the Authority, the higher of the expenditure incurred by \*\*\* and \*\* has been considered.
- c) Export price in case of Russia has been determined on the basis of information compiled by the Directorate of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta. Since none of the exporters from Russia has co-operated with the Authority, export price in case of individual exporters has not been determined. The C&F export prices have been adjusted for ocean freight and commission. The petitioner has claimed ocean freight @ US \$ \*\*\* per MT and commission @ \*\*%. It is, however, found that highest commission paid is \*\*% (by \*\*). It is therefore, considered appropriate to allow freight @ US \$ \*\*\* per MT and commission @ \*\*%.

**J. COMPARISON**

**17. The rules relating to comparison provides as follows:**

"While arriving at margin of dumping, the designated authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

**18. Whereas the argument that the international market was declining is recognised and is well appreciated, the same is irrelevant in so far the**

issue of dumping by an exporter is concerned. The only relevant issue to decide dumping is the pricing of the exporter in the two different markets. The argument of the interested parties that there was no dumping due to the declining international prices, is not tenable. However, the Authority observes that there was significant decline in the prices in the domestic market also in case of Abitibi and Stone Consolidated. Since the prices in the US and Canadian markets were also declining, any comparison on the basis of averages of normal value and export price for the investigation period as a whole could be misleading. The Authority had, even for the purpose of deciding on initiation, made comparison of normal value with export price on month-to-month basis. The Authority observes from the information furnished by Abitibl and Stone Consolidated that it would be appropriate to make comparison of normal value and export price on month-to-month basis. It is also observed that Abitibl and Stone Consolidated have furnished details of all the export transactions made to India. The export price on this basis has been compared with the normal value in US/Canada so that the comparison is done as nearly as possible at the same point of time.

19. Export prfce in case of other exporters has been compared with the normal value on similar lines, i.e., month-to-month basis.
20. The comparison shows the following dumping margins:

(all amounts in US \$ per MT)

SN	Name of the Exporter	NV,EP, DM #	April, 1996	May, 1996	June, 1996	July, 1996	August, 1996	Sept., 1996	October, 1996
1.	Abitibi - exports from USA	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	25	23	nil	32	33	26	67
2.	Abitibi - exports from Canada	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	14	3	(-) 4	34	13	15	67
3.	Stone Consolidated	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	nil	6	0	6	2	(-) 3	nil
4.	Avenor	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	32	51	61	75	nil	nil	nil
5.	Daishowa	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	51	nil	nil	55	nil	nil	nil

SN	Name of the Exporter	NV,EP, DM \$	April	May	June	July	August	Sept.	October
6.	Price & Piece-exports from Canada	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	17	32	30	42	24	51	nil
7.	Price & Piece-exports from USA	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	56	38	nil	nil	nil	nil	nil

# NV: normal value,

EP: export price,

DM: dumping margin as percentage of export price.

Nil figure in respect of dumping margin indicate nil imports resulting in nil dumping margin.

## K. INJURY

21. Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "...taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
22. Rule (iii) of the Annexure II to the Rules requires that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports. Such assessment can be, however, made only if it is determined that:
- the margin of dumping in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the import of the like article in India, and
  - the cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.
- In the present case, the dumping margin in respect of each exporter as also each country is more than the limits prescribed. Further, cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has, therefore, cumulatively assessed the effects of these imports on the domestic industry.
23. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra.
- Volume and Market Share of Dumped Imports  
i) Volume of dumped imports:  
Imports of newsprint in India increased from 217108 MT (1992-93) to 301967 MT (1995-96) and were 382861 MT in the seven months of investigation period (656333 MT on annualised basis). Imports from the

subject countries collectively increased from 108330 MT (1992-93) to 228899 MT (1995-96) and were 284995 MT in the investigation period (488563 MT on annualised basis). Imports from the subject countries increased by 351% in absolute terms in the investigation period as compared to 1992-93, as may be seen from the following figure 1.

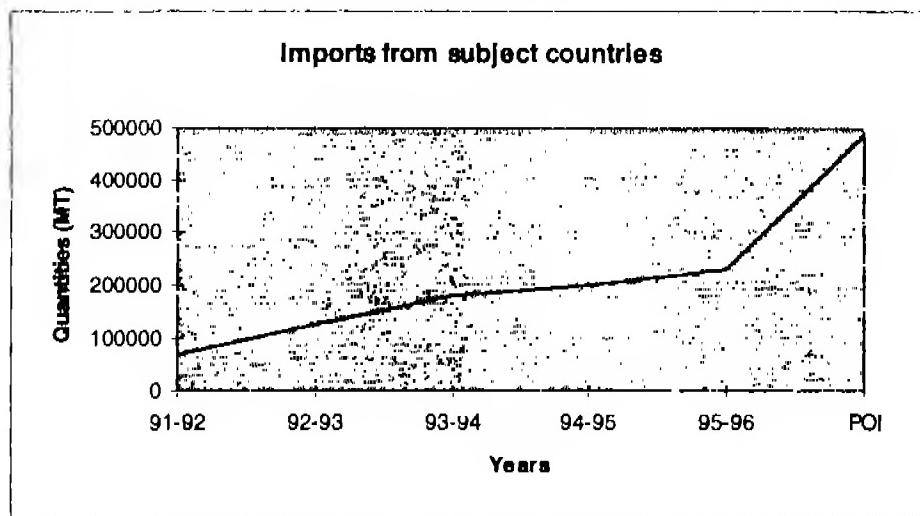


Figure 1 - Imports of newsprint from the subject countries

ii) Market share:

Share of the subject countries in the total imports in the country increased from 50% (1992-93) to 74% (investigation period). Market share of the subject countries in the total demand of newsprint in India increased from 21% (1992-93) to 32% (1995-96) and to 54% in the investigation period as may be seen from the following figure 2.

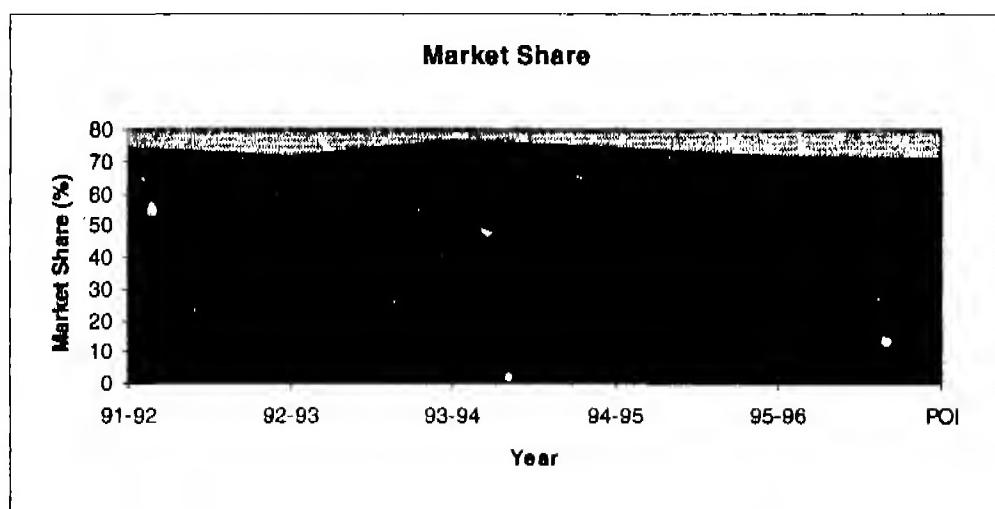


Figure 2 - Market share of imports from the subject countries and sales by the domestic industry

b. Factors affecting domestic industry:

i) Production and Capacity Utilisation:

Production of the domestic industry remained between 2.80 lacs and 2.90 lacs between 1992-93 and 1995-96. The production increased in the investigation period by 12%. It is, however, found that TNPL has added substantial capacity (by 50000MT). Domestic Industry lost market share from 47% (1992-93) to 40% (1995-96). The market share, however, sharply declined to 17% in the investigation period, as may be seen from the figure 2 above.

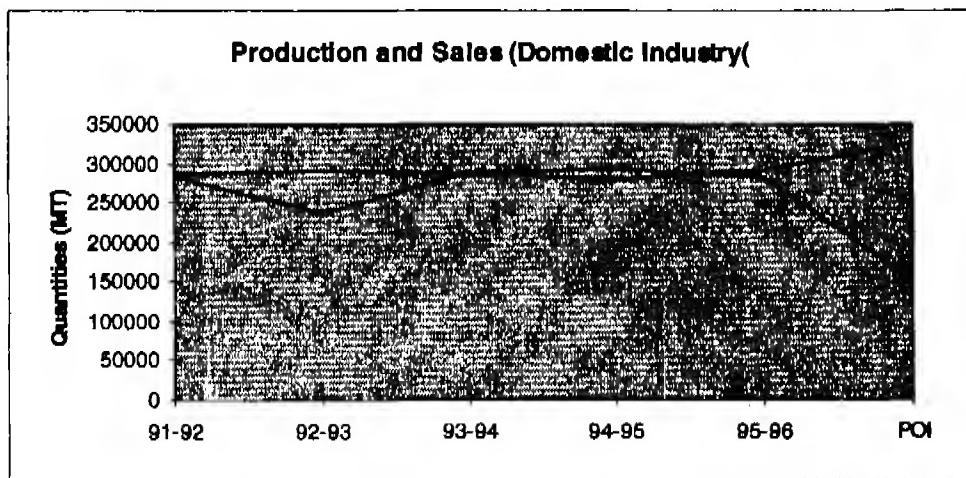


Figure 3 - Production and sales of the domestic industry

Petitioner reported that M/s. Nepa Ltd., Danalakshmi Paper Mills Ltd., and Aurangabad Paper Mills Ltd. have suspended production in view of dumping.

ii) Sales in Absolute Quantity:

Sales of the domestic industry in absolute volumes remained between 2.70 lacs MT and 2.95 lacs MT between 1992-93 and 1995-96. The sales however, sharply declined by 46% in the Investigation period on annualised basis, as may be seen from the figure above.

iii) Selling Prices Trend:

The domestic Industry was not able to sell its produce in view of cheaper imports from the subject countries. The consumers demanded lower prices and higher discounts in view of cheaper produce available from other sources. Increasingly lower prices offered by the exporters in the investigation period forced the domestic industry to offer higher discounts, which resulted in price undercutting in the Indian market. It is also observed that the international prices of major raw material "Pulp" were declining during the Investigation period. However, the available data reveals that the decline in the selling prices in the investigation period is significantly higher than the decline in the cost of production.

- iv) Stocks: Month-end stocks with the domestic Industry indicate increasing trends during the investigation period, as may be seen from the figure 4. Nepa had saleable stocks of newsprint. The shutdown by the company can not be a reason for the exporters to dump the goods in India.

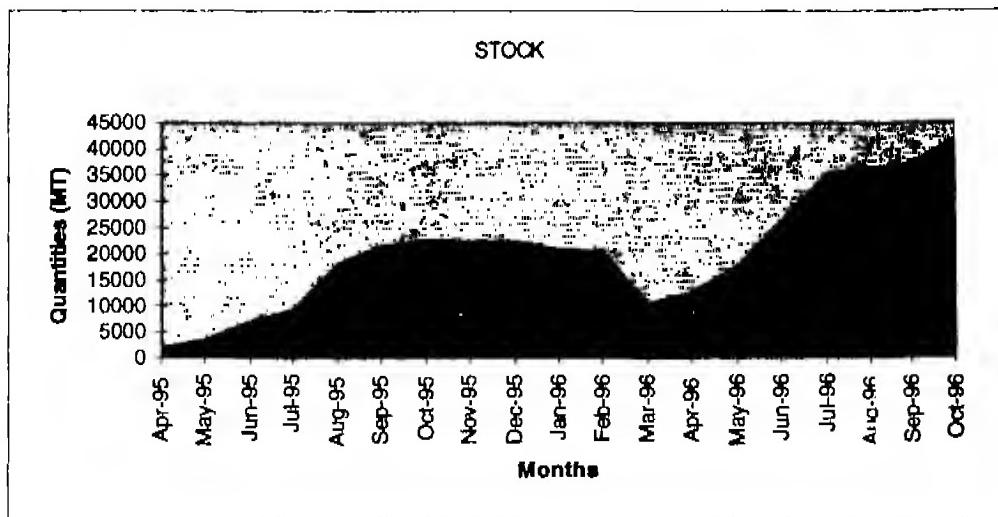


Figure 4 - Stock of newsprint with the domestic industry

- iv) Profit/Loss: The domestic industry was making profit prior to the investigation period. The domestic industry, however, suffered financial losses in the investigation period from sale of newsprint at prices below cost of production with reasonable profits.
- vi) Conclusion on injury: The Authority concludes from the foregoing that:
- The imports from the subject countries have increased in absolute terms;
  - The exporters entered in contracts for supplies of newsprint at increasingly lower rates for deliveries to be made in the subsequent months. This forced the Indian industry to reduce its prices, significantly below cost of production and reasonable profit ;
  - The imports from the subject countries resulted in price undercutting in the Indian market;
  - Sales of domestic industry declined steeply in the investigation period;

- v) Stocks of newsprint with the domestic Industry show increasing trend in the investigation period.
24. It is thus seen the domestic industry has suffered material injury from imports originating from the subject countries.

#### **L. CAUSAL LINK**

25. In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts:
- (i) The imports of the product from the subject countries increased significantly in absolute terms and relative to the production and consumption of the product in India. The share of the subject countries in the total imports also increased significantly. As a direct consequence, the domestic industry lost market to a significant level.
- (ii) The substantial imports of newsprint from the subject countries at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to unremunerative levels and resulted in a situation of price undercutting in the Indian market. The sales below cost of production resulted in financial losses to the domestic industry.
26. The Authority thus arrived to a conclusion that the material Injury to the domestic industry was caused by the dumped imports from the subject countries.

#### **M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

27. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

28. It is recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using newsprint and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of the anti dumping duty is limited to the amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and would not affect the availability of the product to the consumers.
29. To ascertain the extent of Anti-dumping duty necessary to remove the injury to the domestic industry, the Authority has relied upon reasonable selling price of the newsprint in India for the domestic industry, by considering the optimum cost of production and reasonable profit for the domestic industry.
30. The import duty imposed by the Government of India has relevance in determination of the extent of injury suffered by the domestic industry and has been accordingly taken care of.
31. It is appreciated that the newsprint industry is cyclical in nature and has periodical rise and fall. However, dumping is determined with reference to the normal value and export price at nearly same point of time, as brought out above under comparison. The cyclical nature of industry is, therefore, irrelevant for deciding dumping.
32. With regard to confidentiality of information furnished by an interested parties, it is clarified that the rules relating to confidentiality prescribe that in case the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information. There is typographical error in the exporter's questionnaires sent and the word "regard" may be substituted by "disregard".

## N. CONCLUSIONS

33. The Authority concludes, after considering the foregoing, that:
- Newsprint originating in or exported from USA, Canada and Russia has been exported to India below its normal value, resulting in dumping;
  - Imports of newsprint from these countries have caused material injury to the domestic industry;

- c. The injury has been caused by the imports from the subject countries.
34. It is considered necessary to impose anti dumping duties provisionally, pending final determination, on all imports of newsprint originating in or exported from the subject countries in order to remove material injury to the domestic industry, pending investigation.
35. It was considered whether a duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury. The weighted average landed price of the imports for each exporter, for the purpose, was compared with the fair selling price of the domestic industry, determined for the period of investigation. Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended. Accordingly, the Authority recommends that provisional anti dumping duties, as set out below be imposed, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of newsprint, falling under Chapter 48 of the Customs Tariff, originating in or exported from these countries, pending final determination.

Products originating in or exported from	Name of the exporter	Amount of Duty (Rs. per MT)
1. USA	a. Abitibi-Price Inc.	6250
	b. Price & Piece,	2513
	c. Exporters other than above	6250
2. Canada	a. Abitibi-Price Inc.	3089
	a. Stone Consolidated Corpn.	1041
	b. Daishowa Forest Products	2692
	c. Price & Piece,	5160
3. Russia	d. Exporters other than above	5160
	Any exporter	3191

36. The known exporters, importers, petitioners and other interested parties are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the despatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.

DIPAK CHATTERJEE, Designated Authority